projects and decision taken thereon are as under:—

(i) Manmad-Aurangabad — Parbhani-Parli-vaijnath Conversion of MG line into B.G.

This is an approved project and work on 1st phase from Manmad to Aurangabad is in progress. Funds are being allotted according to overall availability of resources.

(ii) Adilabad-Pimpalkutti new BG line.

This is an approved work. It is also being progressed according to overall availability of funds.

(iii) Parbhani-Nanded conversion from MG to BG, new line from Nanded to Gangakhed and conversion of MG line to BG from Gangakhed to Parlivaijnath.

Conversion of Parbhani to Nanded is approved as part of Parbhani-Adilabad conversion project which will be taken up when resource position improves. Conversion of Gangakhed—Parli-Vaijnath is part of approved project at S.No. (i) above. It has not been possible to approve new line from Nanded to Gangakhed due to constraint of resources.

(iv) New B.G. line from Latur road to Latur and conversion of Latur-Miraj N.G. line into B.G.

It has not been possible to approve this work due to severe constraint of resources.

**Foreclosure of Mortgages of ships**

2454. SRHI MOSTAFA BIN QUASEM: Will the Minister of TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government have decided on the foreclosure of mortgages in respect of ships of certain companies;

(b) if so, how those ships are going to be managed;

(c) whether a new shipping organisation is proposed to be constituted; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF TRANSPORT (SHRI BANSI LAL): (a) Yes, Sir.

(b) During pendency of Court proceedings, the Court appoints, on the applications of the Shipping Development Fund Committee, a Receiver to manage the ships, such as Shipping Corporation of India|Mogul Line Limited or any other suitable agency.

(c) There is no such proposal before Government at present.

(d) Does not arise.

**पुरानी दिल्ली में क्षय रोगियों का प्रतिशत**

2455. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन द्वारा किए गये एक सर्वेक्षण के अनुसार पुरानी दिल्ली में क्षय रोगियों की संख्या ऐसे रोगियों की राष्ट्रीय औसत से 8 से 10 गुणा अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्षय रोगयों का राष्ट्रीय औसत प्रति हजार कितना है और पुरानी दिल्ली में क्षय रोगियों का औसत प्रति हजार कितना है;

(ग) इन रोगियों में अधिकतर किस आय, वर्ग के लोग आते हैं; और

(घ) सरकार उक्त क्षेत्र में क्षय रोग की रोकथाम के लिए क्या कदम उठा रही है ?

**परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री ( श्री कृष्ण कुमार ) :** ( क ) दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने रोग की व्यापकता के बारे में कोई वैज्ञानिक सर्वेक्षण नहीं किया था लेकिन वर्ष 1984 में पुरानी दिल्ली के जामामस्जिद क्षेत्र में केवल

एक स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया था जिसमें रोग के लक्षणों वाले रोगियों को बुलाया गया था और उनकी जांच की गई थी । इन लाक्षणिक रोगियों के जांच-परिणामों को रोग की व्यापकता संबंधी वैज्ञानिक सर्वेक्षण नहीं कहा जा सकता जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि पुरानी दिल्ली में क्षय रोग की व्यापकता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है ।

(ख) और (ग) पुरानी दिल्ली में रहने वाली आम आबादी के बीच वैज्ञानिक आधार पर किए गए नमूना सर्वेक्षणों से पता चला कि 5 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लगभग 1.8 प्रतिशत लोग फेफड़ों के क्षय रोग से पीड़ित थे और उनका यह रोग रेडियो लोजिकल रूप से सक्रिय था । इनमें से लगभग एक चौथाई अर्थात 0.4 प्रतिशत रोगी ही थूक पाजिटिव अथवा संक्रामक थे । इस सर्वेक्षण से यह भी पता चला कि क्षय रोग की व्यापकता जनसंख्या के उन वर्गों में बहुत अधिक है जो "कच्चे मकानों" में रह रहे हैं और जिनकी सामाजिक स्थिति असंतोषजनक है ।

(घ) दिल्ली में क्षय रोगियों को निःशुल्क निदान और उपचार, जिसमें क्षय रोगरोधी औषधियों की व्यवस्था भी शामिल है, की सुविधाएं 13 क्षय रोग क्लीनिकों और 2 प्रमुख क्षय रोग अस्पतालों के जरिए उपलब्ध हैं ।

**Demand by States for more Central assistance for education**

2456. SHRI K. VASUDEVA PANICKER: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the State Governments have demanded more Central assistance for education; and

(b) whether the demand has been taken care of during the Seventh Five Year Plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE (SMT. SUSHILA ROHATGI): (a) Yes, Sir.

(b) While finalising the Seventh Plan proposals on Education, the requirements of the States have been taken into account keeping in view the constraints on resources.

**वाराणसी-कैंट रेलवे स्टेशन पर धन का कथित कुप्रबन्ध**

2457. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर निर्माण-कार्य में लाखों रुपयों का कथित घपला किये जाने के सम्बन्ध में वाराणसी से प्रकाशित होने वाले हिन्दी दैनिक "आज" दिनांक 23 अक्तूबर, 1985 में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया)**: (क) और (ख). 20-10-85 के समाचार पत्र में छपी खबर में उल्लेख किया गया है कि वाराणसी कैंट स्टेशन पर प्लेटफार्म के नवीकरण का काम सही ढंग से नहीं किया गया है और बड़ी लाइन के घूमने योग्य एप्रेन में दरारें आ गई हैं ।

(ग) इस स्टेशन पर, हाल ही में प्लेटफार्म का विस्तार किया गया है जो इस काम के लिए विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार है। बड़ी लाइन पर घूमने योग्य एप्रेन का निर्माण 1972 में किया गया था । धसन आदि के कारण इसमें दिखायी देने वाली दरारों की मरम्मत कर दी गयी है ।